

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

देहरादून: दिनांक 20 फरवरी, 2015

राजस्व अनुभाग-2

विषय:-जनपद बागेश्वर में नगर पंचायत, कपकोट के निर्माण हेतु कुल 0.400 है० भूमि शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-350/पी०ओ०-एल०बी०सी०/2014 दि०-29.09.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम बमसेरा, रा०उ०नि०क्षे० भराड़ी, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर ज०वि०ख०खा० सं०-82 के खसरा सं०-76 मध्ये 0.340 है० तथा खसरा सं०-95 मध्ये 0.060 है० इस प्रकार कुल 0.400 है० भूमि श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन तथा शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभागीय परामर्श/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के कारण भारत सरकार की पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ही वास्तविक हस्तांतरण किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- प्रश्नगत नॉन जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 व इसके समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।



प्रेषक,
भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 20 फरवरी, 2015

विषय:-जनपद अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई, देहरादून के द्वारा उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (यू0ई0ए0पी0) के अंतर्गत राजकीय भूमि पर हैलीपैड/हैलीपोर्ट/हैलीड्रोम निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-122/ग्यारह-24/2013-14 दि0-20.10.2014 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-5031/रा0प0-भू0हस्तां0 (हैली0अल्मो0)/2014 दि0-18.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, जनपद अल्मोड़ा के ग्राम पेटशाल की नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9(3)ड बं0का0आ0 के ख0खा0 सं0-120 के खेत सं0-5653 मध्ये 0.312 है0 भूमि के साथ बुधोल तोक के नॉन जेड0ए0 ख0खा0 सं0-119 की श्रेणी 9(3)ग गौचर-पशुचर के खेत सं-5701 एवं खेत सं0-5781 मध्ये 0.805 है0 इस प्रकार कुल 1.117 है0 भूमि पर हैलीपैड/ हैलीपोर्ट/हैलीड्रोम निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान करते हैं।

कृपया इस संबंध में सिविल अपील सं0-436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0-जनवरी, 2011 के क्रम में शासनादेश सं0-1332/XVIII(II)/2014-18(59)/2013 दि0-07.07.2014 द्वारा दिये गये आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या-287 /समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 4- कार्यक्रम प्रबंधक, यू0ई0ए0पी0, परियोजना क्रियान्वयन इकाई यूकाडा, दून हैलीड्रोम, ग्राम कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतोष बडोनी)
उप सचिव।